उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

मोहम्मद नईम

(एस.के. दास, ए.के. सरकार, के.एन. वांचू और के.सी. दास गुप्ता, न्यायाधीशगण)

उच्च न्यायालय - आपराधिक मामलों में अंतर्निहित शक्ति - निर्णय में टिप्पणियाँ - न्यायाधीशों के कर्तव्य - टिप्पणियाँ हटाना - उच्च न्यायालय की शक्ति - राज्य सरकार, यदि लागू हो सकती है - दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अधिनियम V/1898), धारा 561-ए।

एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी एन को नोटिस जारी कर यह बताने का निर्देश दिया कि क्यों न उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत शिकायत शुरू की जाए। एन उपस्थित हुआ और उसने खुद को अदालत की दया पर छोड़ दिया और माफ़ी मांगी। उच्च न्यायालय ने माफी को झिझकते हुए स्वीकार कर लिया लेकिन पुलिस बल के खिलाफ अन्य टिप्पणियों के साथ-साथ निम्नलिखित भी कहा।

"(ए) अगर मुझे लगता कि अपने अकेले के प्रयासों से मैं इस गंदे अस्तबल, जो कि पुलिस बल है, को साफ़ कर सकता था, तो मुझे अकेले ही इस युद्ध को लड़ने में संकोच नहीं होता।

(बी) पूरे देश में एक भी अराजक समूह ऐसा नहीं है जिसका अपराध का रिकॉर्ड उस संगठित इकाई के रिकॉर्ड के आसपास भी आता हो जिसे भारतीय पुलिस बल के नाम से जाना जाता है।

(सी) जहां कुछ को छोड़कर हर मछली से बदबू आती है, वहां एक या दो को चुनकर यह कहना बेकार है कि उससे बदबू आ रही है।"

राज्य ने इन टिप्पणियों को फैसले से हटाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि राज्य एक पीड़ित पक्ष नहीं था और उसके पास धारा 561-ए के तहत आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं था और निर्णय से टिप्पणियों को हटाने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं था। उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील पर।

अपील की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार एक पीड़ित पक्ष थी और वह संबंधित टिप्पणियों को हटाने के लिए धारा 561-ए के तहत उच्च न्यायालय में जाने की हकदार थी। राज्य सरकार वह प्राधिकरण है जो राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है, और पुलिस विभाग उसके विभागों में से एक है जिसके माध्यम से कानून और व्यवस्था का सम्मान करने वाली उसकी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राज्य सरकार अपने विभाग या अधिकारियों के विरुद्ध की गई टिप्पणियों से व्यथित हो सकती है। राज्य एक विधिक व्यक्ति है और धारा 561-ए के तहत आवेदन दायर करने का हकदार है। संहिता स्वयं एक पक्ष के रूप में राज्य द्वारा अपील और आवेदन दाखिल करने पर विचार करती है।

धारा 561-ए ने उच्च न्यायालयों को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं की, बल्कि उनकी मौजूदा अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित रखा। उच्च न्यायालय, अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने द्वारा या निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा सकता है, यदि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। क्षेत्राधिकार असाधारण प्रकृति का है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

जयराम दास बनाम एम्परर, ए.आई.आर. (1945) पी.सी. 94 और *एम्परर बनाम नज़ीर अहमद*, ए.आई.आर. (1945) पी.सी.18, का उल्लेख किया गया है।

एम्परर बनाम *चौ. मोहम्मद हसन*, ए.आई.आर. (1943) ला. 298, *राज्य* बनाम *छोटे लाल*, 1955 ए.एल.जे. 240, *ललीत कुमार* बनाम एस.एस. बॉस, ए.आई.आर. (1957) सभी 398, *एस. लाल सिंह* बनाम *राज्य*, ए.आई.आर. (1959) पंजाब 211, *रामसागर सिंह* बनाम *चंद्रिका सिंह*, ए.आई.आर. (1961) पटियाला 364 और *इन री रामास्वामी*, ए.आई.आर. (1958) मद्रास 305, अनुमोदित।

राज्य बनाम *नीलकंठ श्रीपाद भावे*, आई.एल.आर. 1954 बम्बई 148, अनअनुमोदित।

न्याय प्रशासन में यह मूलभूत महत्व का सिद्धांत है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति, स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से और निडरता से और किसी भी निकाय, यहां तक की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए बिना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी उतना ही आवश्यक है कि अपनी राय व्यक्त करते समय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को न्याय, निष्पक्षता और संयम के विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। न्यायिक निर्णय प्रकृति में न्यायिक होनी चाहिए, और आम तौर

पर संयम, संतुलन और संकोच से विचलित नहीं होनी चाहिए। राज्य के संपूर्ण पुलिस बल के संबंध में फैसले में की गई टिप्पणियाँ मामले के तथ्यों पर उचित नहीं थीं, न ही वे मामले के निपटान के लिए आवश्यक थीं और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 81/1962

आपराधिक विविध वाद संख्या 348/1961 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ), लखनऊ के 23 अक्टूबर, 1961 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी की ओर से - सी. बी. अग्रवाल, जी. सी. माथुर, शंकर सहाय और सी. पी. लाल।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीशों की ओर से (नोटिस पर) - जे.पी. गोयल।

1963, 15 मार्च।

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश एस.के. दास द्वारा सुनाया गया।

यह अपील विशेष अनुमति द्वारा की गई है, और यह कुछ असामान्य विशेषताएं दर्शाती है। संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है- उत्तर प्रदेश राज्य में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदोई ने जफर अली खान और तीन अन्य व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और

307 सपठित धारा 34 के तहत आरोपों पर मुकदमा चलाया। उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ मामला शाहाबाद नामक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर शुरू हुआ, 7 और 8 नवंबर, 1958 के बीच की रात को किसी फरासत अली खान द्वारा लगभग 3:30 बजे पूर्वाह्न यह मामला दर्ज कराया जाना तात्पर्यित है। मामले की जांच मोहम्मद नईम नामक व्यक्ति ने की थी जो उस समय शाहाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन अधिकारी थे। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया, हालांकि उन्होंने मामले में दिए गए सबूतों पर पाया कि यह अधिक संभावना थी कि पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी सुबह 3:30 बजे के बजाय लगभग 7 या 8 बजे दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) में अपील की गई। इस अपील की सुनवाई न्यायाधीश मुल्ला ने की। उन्होंने पाया कि मोहम्मद नईम ने पूरी तरह से अविश्वसनीय मामला बनाया था, जिसने अभियोजन पक्ष के दो प्रमुख गवाहों, फरासत अली और उनकी पत्नी, उम्मती बेगम के बयानों के साक्ष्य मूल्य को नष्ट कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने अपील की अनुमति दी और अपने समक्ष आए चार अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में आगे कहा:

"यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट सुबह 3:30 बजे दर्ज नहीं की गई थी। यही निष्कर्ष विचारण न्यायालय का भी है। इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित समय एक काल्पनिक समय है और सार्वजनिक अभिलेख में फर्जीवाड़ा किया गया है। इसलिए, मैं कार्यालय को श्री मोहम्मद नईम को नोटिस जारी करने का निर्देश देता हूं कि इस न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 195 के तहत उनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं संस्थित की जानी चाहिए।"

विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में, मोहम्मद नईम को कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज किये जाने के कथित समय के संबंध मे किये गए फर्जीवाड़े के लिए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत अपराध की शिकायत क्यों नहीं संस्थित की जानी चाहिए। मोहम्मद नईम विद्वान न्यायाधीश के सामने पेश हुए और खुद को न्यायालय की दया पर छोड़ दिया और माफ़ी मांगी। विद्वान न्यायाधीश ने आपराधिक विविध वाद संख्या 87/1961 में मामले का निपटारा किया। उन्होंने मोहम्मद नईम की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन कहा

कि उन्होंने ऐसा बहुत झिझकते हुए किया। अपने आदेश के दौरान मोहम्मद नईम की माफ़ी स्वीकार करते हुए उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ कीं। अभी हम उन टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैं:-

> "मैंने नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि मैं लोक प्रशासन को यथासंभव स्वच्छ बनाना चाहता हूं लेकिन किसी एक व्यक्ति के प्रयास दूरगामी नहीं हो सकते है। अगर मुझे लगता कि अपने अकेले प्रयासों से मैं इस गंदे अस्तबल, जो कि पुलिस बल है, को साफ़ कर सकता हूँ, तो मुझे अकेले ही यह युद्ध लड़ने में कोई झिझक नहीं होती। मैं सेवानिवृत्ति के कगार पर हूं और दो महीने या तीन महीने और ऐसे कदम उठाने से संविधान और पुलिस बल के चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा..... किसी तरह, कुछ अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर पुलिस बल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपराध की जांच नहीं की जा सकती है और कानून का पालन करके सुरक्षा को संरक्षित नहीं किया जा सकता है और यह केवल कानून को तोड़कर या उसे दरकिनार करके ही हासिल किया जा सकता है। कम से कम सौ वर्षों

की परंपराएँ तो यही बताती हैं कि वे यही मानते हैं। यदि उनके मन से यह धारणा जड़ से खत्म नहीं होती है तो सुधार की संभावना कम ही है..... मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे देश में एक भी अराजक समूह ऐसा नहीं है जिसका अपराध का रिकॉर्ड उस संगठित इकाई के रिकॉर्ड के आसपास भी हो जिसे भारतीय पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। यदि पुलिस बल को मोहम्मद नईम जैसे अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए तो बेहतर होगा कि हम अपने संविधान को फाड़ दें, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों के बारे में सब कुछ भूल जाएं और न केवल हमारे दंड अधिनियमों में बल्कि हमारे शब्दकोशों में भी कानून और अन्य शब्दों के अर्थ को बदल दें।

इन्हीं कारणों से मैं इस माफी को स्वीकार कर रहा हूं और मोहम्मद नईम के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा हूं। जहां कुछ को छोड़कर हर मछली से बदबू आती है, वहां एक या दो को चुनकर यह कहना बेकार है कि इसमें से बदबू आ रही है।

इसलिए, मैं श्री मोहम्मद नईम के खिलाफ जारी नोटिस को खारिज करता हूं।"

उत्तर प्रदेश राज्य ने उपरोक्त कुछ टिप्पणियों से असंतुष्ट महसूस किया और उन्हें हटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत एक आवेदन किया। जिन टिप्पणियों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य ने असंतुष्ट महसूस किया, उन्हें याचिका के पैरा 4 में शीर्षक (ए), (बी) और (सी) के तहत समूहीकृत किया गया था, जिसे अब हम यहां प्रस्तुत कर सकते हैं:

(ए) "अगर मुझे लगता कि अपने अकेले प्रयासों से मैं इस गंदे अस्तबल, जो कि पुलिस बल है, को साफ़ कर सकता था, तो मुझे अकेले ही इस युद्ध को लड़ने में संकोच नहीं होता।"

(बी) "पूरे देश में एक भी अराजक समूह ऐसा नहीं है जिसके अपराध का रिकॉर्ड उस संगठित इकाई के रिकॉर्ड के आसपास भी आता हो जिसे भारतीय पुलिस बल के नाम से जाना जाता है।"

(सी) "जहां कुछ को छोड़कर हर मछली से बदबू आती है, वहां एक या दो को चुनकर यह कहना बेकार है कि इससे बदबू आ रही है।"

उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी याचिका के समर्थन में जिसे मुख्य आधार बताया था, वह यह था कि "पूरे पुलिस बल पर की गई टिप्पणियाँ, इसे अवमानना मे लाती हैं, मानव जाति की नज़र में उसकी प्रतिष्ठा को कम करती हैं, देश के प्रशासन में हस्तक्षेप करती हैं और राज्य की सुरक्षा को क्षति पाहुचाती हैं।" राज्य ने आगे अभिकथन किया कि की गई टिप्पणियाँ मोहम्मद नईम को जारी किए गए नोटिस पर विद्वान न्यायाधीश के मुख्य आदेश का आवश्यक हिस्सा नहीं थीं और उन्हें इससे अलग किया जा सकता था और अभिलेख में किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं था जिसको उन टिप्पणियों का आधार बनाया जा सके।

न्यायाधीश मुल्ला ने आवेदन पर सुनवाई की और निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष पर पहुंचे:-

(1) कि उत्तर प्रदेश राज्य एक पीड़ित पक्ष नहीं था और की गई टिप्पणियों के संबंध में धारा 561-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं था।

(2) टिप्पणियों में केवल एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, कि वे उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के संबंध में की गई थीं, न कि पूरे देश के संबंध में।

(3) यदि पीड़ित पक्ष ने विद्वान न्यायाधीश से अनुरोध किया होता तो उपरोक्त (ए) के तहत की गई टिप्पणियों को हटा दिया गया होता।

(4) बाकी टिप्पणियों के संबंध में, उन्हें हटाने का कोई अच्छा आधार नहीं था क्योंकि वे विद्वान न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव पर आधारित थे और उनमें कोई अतिरंजित बयान शामिल नहीं थे।

उन्होंने तदनुसार राज्य के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 134(आई) (सी) के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और वहां असफल होने पर, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय से विशेष अनुमति मांगी। वर्तमान अपील धारा 561-ए सीआर.पी.सी. के तहत आवेदन को खारिज करने वाले विद्वान न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध, इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में गई है।

पहला बिंदु जो विचारणीय है वह यह है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य को सीआर.पी.सी की धारा 561-ए के तहत आवेदन करने का अधिकार है। हम पहले धारा को पढ़ सकते हैं:

> "इस संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करता हो, या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए।"

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक (अन्य उद्देश्यों के साथ) उच्च न्यायालय के पास मौजूद सभी मौजूदा अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा करता है। धारा में प्रावधान है कि जो शक्तियां न्यायालय के पास स्वाभाविक रूप से हैं, उन्हें संरक्षित रखा जाएगा, ऐसा न हो कि यह माना जाए कि अदालत के पास केवल वही शक्तियां हैं जो स्पष्ट रूप से संहिता द्वारा प्रदत्त हैं और कोई भी अंतर्निहित शक्ति संहिता के पारित

होने से अस्तित्व मे नहीं है (देखें: *जयराम दास* बनाम *एम्परर*[1], और *एम्परर* बनाम *नज़ीर अहमद*[2]। वर्तमान में हम इस प्रश्न से निपटेंगे कि क्या उच्च न्यायालय के पास किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उसके द्वारा या निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित शक्ति है। यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है, अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के इस अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है? उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष, कि राज्य सरकार के पास सीआर.पी.सी. की धारा 561-ए के तहत आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है, के लिए दो कारण बतायें। उन्होंने पहला कारण यह बताया कि यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार उनके द्वारा की गई टिप्पणी से व्यथित है। उन्होंने दूसरा कारण यह बताया कि राज्य ने कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायपालिका का भी प्रतिनिधित्व किया और इसलिए यदि वह सीआर.पी.सी. की धारा 561-ए के तहत आवेदन करता है तो यह विलक्षण होगा, क्योंकि ऐसा आवेदन राज्य द्वारा अपनी कार्यपालिका के माध्यम से अपने द्वारा न्यायपालिका के रूप में की गई टिप्पणियों को हटाना होगा।

---

1 ए.आई.आर. (1945) पी.सी. 94

2 ए.आई.आर. (1945) पी.सी. 18

हमें नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी आधार तर्कसंगत है। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और इसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" का एक अर्थ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (X/1897) के तहत दिया गया है। संक्षेप में कहा गया है, इसका मतलब है राज्य में कार्यकारी सरकार का संचालन करने के लिए प्रासंगिक तिथि पर अधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति, और संविधान के लागू होने के बाद इसका मतलब राज्य का राज्यपाल होता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पुलिस विभाग राज्य सरकार का एक विभाग है जिसके माध्यम से कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि राज्य सरकार यह समझती है कि किसी विभाग या अधिकारियों, जिनके माध्यम से राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है, के संबंध में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ ऐसी हैं कि सीआर.पी.सी. की धारा 561-ए के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को लागू करने की आवश्यकता है, तो यह यह समझना कठिन है कि राज्य सरकार को ऐसी टिप्पणियों से पीड़ित पक्ष क्यों नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि राज्य एक विधिक व्यक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता स्वयं अपने कुछ उपबंधों में राज्य सरकार के

अधिकारों को मान्यता देती है; जैसे, मंजूरी देने का अधिकार और आवश्यक कार्यवाही के लिए न्यायालय जाने का अधिकार आदि राज्य सरकार प्रासंगिक तिथि पर कार्यकारी सरकार का संचालन करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति है। इनमें से कुछ प्रावधान संहिता की धारा 144 (6), 190 (2), 190 (3), 196, 196-ए, 197 आदि में निहित हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण संहिता की धारा 417 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है। यह भी विवादित नहीं है कि राज्य सरकार संहिता की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है, हालांकि वह धारा अपनी शर्तों में सामान्य है और विशेष रूप से राज्य सरकार का उल्लेख नहीं करती है। इसलिए, हम यह समझने में असफल हैं कि राज्य सरकार धारा 561-ए के तहत आवेदन क्यों नहीं कर सकती। जब राज्य सरकार अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों से व्यथित महसूस करती है तो निवारण के लिए अदालत का रुख करने में हमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। राज्य सरकार धारा 561-ए के तहत उच्च न्यायालय में उसी तरह आवेदन कर सकती है जैसे वह लोक अभियोजक को धारा 417 के तहत अपनी ओर से उच्च न्यायालय में अपील पेश

करने का निर्देश दे सकती है या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से संहिता की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि राज्य सरकार के पास सीआर.पी.सी. की धारा 561-ए के तहत आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है, कानून की दृष्टि से गलत है। हमारा ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर आकर्षित किया गया जहां राज्य सरकार ने लंबित अपील में ऐसे आवेदन किए थे। हालाँकि, इसमें कोई सवाल नहीं उठाया गया था कि क्या राज्य सरकार के पास आवेदन करने का अधिकार था; इसलिए, हमने उन मामलों, जहां ऐसे आवेदन किए गए थे, के बजाय सिद्धांत पर बिंदु को तय करना उचित समझा है।

विचारणीय दूसरा बिन्दु यह है, क्या उच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए स्वयं या निचले न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित शक्ति है? एक समय इस प्रश्न पर न्यायिक राय में कुछ मतभेद था। निर्णय-विधि के बारे में स्थिति अब यह प्रतीत होती है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कुछ हद तक प्रतिबंधित दृष्टिकोण को छोड़कर, अन्य उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया है कि यद्यपि क्षेत्राधिकार एक असाधारण

प्रकृति का है और इसका प्रयोग सबसे असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय किसी फैसले से टिप्पणियों को हटाने के लिए निस्संदेह स्वतंत्र है। [देखें- *एम्परर* बनाम *चौ. मो. हसन*[3]; *राज्य* बनाम *छोटे लाल* [4]; *ललित कुमार* बनाम *एस.एस. बोस*[5]; *एस. लाल सिंह* बनाम *राज्य*[6]; *रामसागर सिंह* बनाम *चंद्रिका सिंह*[7]; और *इन री रामास्वामी*[8]]. बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपनाया गया दृष्टिकोण यह है कि उच्च न्यायालय के पास निचले न्यायालय के फैसले से उन अंशों को हटाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो नियमित अपील या पुनरीक्षण में उसके समक्ष नहीं लाए गए हैं; लेकिन सीआर.पी.सी. की धारा 561-ए के तहत एक आवेदन विचार योग्य है और एक उचित मामले में उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है, भले ही इसमें कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाता है, न्यायिक रूप से की गई टिप्पणियों को सही करने के लिए यह इंगित करके कि वे उचित नहीं थे, या निराधार थे, या पूरी तरह गलत या अनुचित थे [देखें- *राज्य*

---

3 ए.आई.आर. (1943) ला. 298

4 1995 ए.एल.जे. 240

5 ए.आई.आर. (1957) इलाहाबाद 998

6 ए.आई.आर. (1959) पंजाब 211

7 ए.आई.आर. (1961) पट. 364

8 ए.आई.आर. (1958) मद्रास, 305

बनाम *नीलकंठ श्रीपाद भावे*[9]]। *यूपी राज्य* बनाम *जे.एन. बग्गा*[10] के मामले मे, इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया।यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपीलीय निर्णय और आदेश के खिलाफ इस अदालत में लाई गई एक अपील में दिया गया था। *यू.पी. राज्य* बनाम *इब्राहिम हुसैन*[11] के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में की गई कुछ टिप्पणियाँ करना आवश्यक नहीं था। यहां फिर से उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश की अपील में यह टिप्पणी की गई। हमारा मानना है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के अलावा अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा या निचले न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा सकता है यदि अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो; हालाँकि अधिकार क्षेत्र असाधारण प्रकृति का है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के प्रति निष्पक्षता में

---

9 आई.एल.आर. 1954 बम्बई 148

10 सीआर.ए. 122/1959 में 16 जनवरी 1961 को इस न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय।

11 सीआर.ए. 148/1957 एवं 4/1958 मे 28 अप्रैल 1959 को इस न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय।

हम यहां बता सकते हैं कि उन्होंने हमारे सामने तर्क दिया है कि राज्य सरकार संतुष्ट होगी यदि हम या तो टिप्पणियों को हटा दें या उन्हें मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से अनुचित मानें। उन्होंने कहा है कि अपील का वास्तविक उद्देश्य जिन टिप्पणियों से पूरे राज्य के पुलिस बल पर कलंक लगा है उसे दूर करना है, जिनकी सच्चाई को चुनौती देने का उसके पास कोई अवसर नहीं था।

अंतिम प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामला असाधारण प्रकृति का मामला है जिसमें विद्वान न्यायाधीश को राज्य सरकार द्वारा शिकायत की गई टिप्पणियों के संबंध में सीआरपीसी की धारा 561-ए के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था? यदि न्याय प्रशासन में मूलभूत महत्व का एक सिद्धांत है, तो वह यह है: न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की उचित स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से और निडरता से करने की अनुमति दी जानी चाहिए और किसी भी निकाय, यहां तक की इस न्यायालय द्वारा भी अनुचित हस्तक्षेप के बिना। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को अपनी राय व्यक्त करते समय न्याय, निष्पक्षता और संयम के विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। यह अक्सर नहीं होता है कि व्यापक सामान्यीकरण उस उद्देश्य को ही विफल कर देते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है।

न्यायिक रूप से यह माना गया है कि ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में जिनका आचरण न्यायालयों द्वारा तय किए जाने वाले मामलों में विचाराधीन है, यह विचार करना प्रासंगिक है (ए) क्या वह पक्ष जिसका आचरण संदेह के घेरे में है अदालत के समक्ष है या उसके पास स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने का अवसर है; (बी) क्या उस आचरण पर टिप्पणियों को उचित ठहराने वाले अभिलेख पर कोई सबूत है; और (सी) क्या मामले के निर्णय के लिए, उसके अभिन्न अंग के रूप में, उस आचरण पर टिप्पणी करना आवश्यक है। यह भी माना गया है कि न्यायिक निर्णय प्रकृति में न्यायिक होनी चाहिए, और आम तौर पर संयम, संतुलन और संकोच से विचलित नहीं होने चाहिए।

हमारे समक्ष मामले में विद्वान न्यायाधीश ने राज्य के संपूर्ण पुलिस बल के विरुद्ध व्यापक और सामान्य टिप्पणियाँ करने का निर्णय लिया। उनके समक्ष मामला केवल एक पुलिस अधिकारी, मोहम्मद नईम, से संबंधित था, जिनके आचरण के बारे में विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियाँ करना निस्संदेह उचित था। विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं महसूस किया कि उन्होंने जो टिप्पणियाँ की थीं, वे बहुत सामान्य थीं और चरित्र में व्यापक थीं, क्योंकि अपने बाद के आदेश में उन्होंने कहा था कि टिप्पणियाँ केवल उत्तर प्रदेश में पुलिस बल के लिए थीं

और उन्होंने आगे कहा कि वह पहले उल्लिखित शीर्षक (ए) के तहत की गई टिप्पणियों को हटा देते, यदि पीड़ित पक्ष उसके समक्ष आया होता। हम मानते हैं कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा राज्य के संपूर्ण पुलिस बल के संबंध में की गई टिप्पणियाँ मामले के तथ्यों पर उचित नहीं थीं, न ही वे उनके समक्ष मामले के निपटारे के लिए आवश्यक थीं। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि उनके द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियाँ अभिलेख में मौजूद किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं थीं; उन्होंने कहा कि मुख्यतया बार और बेंच में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह टिप्पणी की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष काफी स्पष्ट रूप से कहा है कि विद्वान न्यायाधीश को आपराधिक मामलों के मामले में बहुत अच्छा अनुभव था, और वह स्थानीय पुलिस द्वारा अपनाई गई जांच की पद्धति से परिचित थे। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया है कि न्यायाधीश के लिए इस मामले में अपने व्यक्तिगत ज्ञान को शामिल करना उचित नहीं था। हमें नहीं लगता कि वर्तमान मामले में हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किस हद तक साक्ष्य का मूल्यांकन या परख करने या यहां तक कि किसी व्यक्ति के आचरण का आकलन करने में अपने अनुभव का उपयोग कर सकता है। हम ऐसे मामले में असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व को पहचानते हैं जहां

न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करना पड़ सकता है कि व्यक्ति और मामले के संबंध में सामान्य या साधारण आचरण क्या है। हम इसे सम्मान के साथ कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में भी उस व्यापक अनुभव को स्वीकार करते हुए जो विद्वान न्यायाधीश को आपराधिक मुकदमों के मामले में मिला था, उनका यह कथन कि "पूरे देश में एक भी अराजक समूह नहीं रहा जिसका अपराध का रिकॉर्ड उस संगठित इकाई के रिकॉर्ड के करीब है, जिसे भारतीय पुलिस बल के रूप में जाना जाता है" पूरी तरह से अनुचित था और, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो यह न्यायिक दृष्टिकोण और संयम की कमी को दर्शाता है। विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी किसी सामग्री का उल्लेख नहीं किया जिस पर यह टिप्पणी आधारित थी, न ही उन्होंने यह कहा कि आपराधिक मुकदमों के उनके अनुभव ने उन्हें पुलिस बल के साथ राज्य में विभिन्न अराजक समूहों के अपराध के रिकॉर्ड की तुलना करने का अवसर दिया। राज्य के पूरे पुलिस बल को एक अराजक समूह के रूप में चित्रित करना काफी बुरा है; यह कहना कि इसका अपराध का रिकॉर्ड राज्य में सबसे अधिक है, बदतर है और जैसा कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है, इससे कानून और व्यवस्था के पूरे प्रशासन की बदनामी होना तय है। ऐसी प्रकृति के व्यापक सामान्यीकरण के लिए, एक निश्चित

आधार होना चाहिए और मामले की आवश्यकता द्वारा इसकी मांग की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में हम दोनों में से किसी को भी नहीं पाते हैं।हमारा मानना है कि राज्य सरकार इस तरह की व्यापक टिप्पणी से उचित रूप से व्यथित थी। "शायद" शब्द से प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के बारे में भी विद्वान न्यायाधीश को कुछ संदेह था। हम मानते हैं कि ये व्यापक सामान्यीकरण अपने स्वयं के उद्देश्य को विफल करते हैं। मोहम्मद नईम के खिलाफ मामले के निपटारे के लिए वे आवश्यक नहीं थे। विद्वान न्यायाधीश के लिए यह कहना काफी होता कि जब बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी अनुसंधान के आपत्तिजनक तरीके का सहारा ले रहे थे, तो एक छोटे अधिकारी को चुनना और उस पर वह काम करने के लिए मुकदमा चलाना अनावश्यक था जो कई अन्य लोगों ने बेख़ौफ़ होकर किया था। विद्वान न्यायाधीश के लिए पूरे पुलिस बल की निंदा करना और यह कहना कि उनका अपराध का रिकॉर्ड देश में सबसे ज्यादा था, पूरी तरह से अनावश्यक था। इस तरह की टिप्पणी पुलिस बल में सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय, जो कि विद्वान न्यायाधीश का कहना है कि उनके मन में था, संभावित रूप से पूरे पुलिस बल की कार्यक्षमता को कमजोर करती है। हमारा मानना है कि पुलिस बल में सुधार के प्रति अपने उत्साह और आग्रह में, विद्वान न्यायाधीश ने खुद को ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करने की अनुमति दी, जिससे उनके

मन में निहित उद्देश्य ही विफल हो गया। यह सब कहने के बाद, हमें यह जोड़ना चाहिए, ताकि हमें गलत न समझा जाए, कि मोहम्मद नईम और उनके जैसे अधिकारियों का आचरण कड़ी निंदा का पात्र है, और विद्वान न्यायाधीश ने ठीक ही कहा कि इस तरह के आचरण के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत गंभीर नोटिस की आवश्यकता होती है। इस विचार से बचना मुश्किल है कि जब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक उदाहरण नहीं बनाया जाएगा, तब तक पुलिस प्रशासन में कोई सुधार संभव नहीं है।

ऊपर दिए गए कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, एक निष्कर्ष जो न्याय की मांग है, कि वर्तमान मामला उन असाधारण मामलों में से एक है जहां न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए था और पूर्व मे की गई (ए), (बी), और (सी) के रूप में संदर्भित टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए था। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि उपरोक्त टिप्पणीयाँ विद्वान न्यायाधीश के 4 अगस्त, 1961 के आदेश से हटाई जाती हैं।

अपील की अनुमति दी जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।